(c) Three meetings of the Committee were held during 1993 on 26-3-1993, 30-9-93 and 30-12-1993.

Land acquired by Mahanadi Coalfields Limited

4286. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) the details of land acquired from the farmers by Mahanadi Coalfields Limited during the last three years ;

(b) the number of farmers whose land has been acquired on account of this :

(c) the steps taken to provide job compensation etc. to the farmers or their dependents ; and

(d) the details of the steps taken in that direction by Mahanadi Coalfields Limited during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Piparwar Coal Project

4287. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Piparwar coal project of Central Coalfields Limited has become ruined by environmental and human rights protests ; and

(b) if so, what steps have been taken by C.C.L. for environmental protection and rehabilitation of displaced villagers in view of this project with details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) and (b) The Piparwar Integrated mine cum-beneficiation project of Central Coalfields Limited which is under implementation is on schedule.

The various environmental protection measures undertaken as per the Environmental Management Plan approved inter-alia, includes reclamation, waste water management, dust suppression, monitoring of air, water and noise, rehabilitation, tree plantation etc.

देश में कोककारी (कोकिंग) कोयले का उत्पादन और मांग

4288. **श्री बीरन जे० शाह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार का ध्यान 5 सितम्बर, 1993 के फाइनेन्सियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "एक्शन प्लान' टू कट कोल इम्पोर्टस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि पिछले कई वर्षों से देश में कोककारी कोयले की मांग में वृद्धि हो रही हैं और दूसरी ओर देश मे कुल कोयले के उत्पादन से कोककारी कोयले के उत्पादन के प्रतिशत में कमी आ रही है ;

(ग) यदि हां, तो 1989-90 से 1993-94 तक इसके उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने देश में आवश्यकता के अनुरुप मांग को पूरा करने हेतु कोककारी कोयले की आपूर्ति करने के लिए एक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं पचवर्षीय योजना के अंत तक देश मे कोककारी कोयले की कुल मांग का कितना प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) धुले हुए कोककर कोयले की इस्पात संयत्रों द्वारा अपेक्षित मांग में वर्ष 1989-90 में लगभग 15.07 मि० टन से 1993-94 में 20.91 (अनंतिम) मि० टन तक की वृद्धि हुई है । इसी अवधि के दौरान इस्पात संयंत्रों को धुले तथा सीधे फीड कोयले की देशीय आपूर्ति में वर्ष 1989-90 में 11.40 मि० टन से 1993-94 में 13.75 (अनंतिम) मि० टन तक की वृद्धि हुई है ।

(घ) जी, हां । एक तकनीकी दल, जोकि कोयला मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था, ने इस्पात संयंत्रों द्वारा अपेक्षित धुले कोयले की देशीय आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के लिए एक कार्रवाई योजना की सिफारिश की है । इस दल की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और को० इं० लि० से एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर कार्रवाई योजना को क्रियान्वित किए जाने के लिए कहा गया हैं ।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रक्षेपणों के अनुसार इस्पात संयंत्रों के लिए धुले हुए तथा सीधे फीड कोककर कोयले की किस्मों की घरेलू उपलब्धता वर्ष 1996-97 के अंत तक लगभग 17.50 मि० टन होगी और यह इस वर्ष में इस्पात संयंत्रों की कुल आवश्यकताओं की लगभग 75% आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी ।

कोयला कंपनियों में उत्पादन लागत में भिन्नता

4289. **श्री ईशदत्त यादव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी कोयला कंपनियों मे उत्पादन लागत एक समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त उत्पादन लागत सरकार द्वारा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के मानकों के आधार पर नियत की गई नियामक लागत से अधिक है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों में कोयले की औसत उत्पादन लागत को नीचे दर्शाया गया है :—

(रुपए/टन में)

कंपनी	औसत उत्पादन लागत
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०को०लि०)	597.90
भारत कोकिंग कोल लि० (भा०को०को०लि०) .	499.03
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (सें० को० लि०) . .	313.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० (ना० को०लि०) . .	239.37
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (वे०को०लि०) .	354.52
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (सा०ई०को०लि०) .	255.46
महानदी कोलफील्ड्स लि० (म०को०लि०) . .	148.65
कोल इंडिया लि० में औसत उत्पादन लागत (को०इं०लि०)	334.31
सिंगरेनी कोलियरीज कं०लि० (सिं० को०कं०लि०) में औसत उत्पादन लागत . .	491.98

(ग) सरकार विनियमन अथवा नियामक लागत निर्धारित नहीं करती है । सरकार द्वारा केवल कोयला कंपनियों द्वारा प्रभार-योग्य कोयले की कीमतें ही निर्धारित की जाती है । को०इं०लि० और सिं० को० कं० लि० के मामले में उस समय विद्यमान औसत कीमतें, जोकि 17-2-1993 को संशोधित की गई थीं, 364 रुपए तथा 434 रुपए प्रति टन थी । उपर्युक्त से यह पता चलता है कि को० इं० लि० के मामले में यह कीमत वर्ष 1992-93 की उसकी औसत उत्पादन लागत से अधिक थी जबकि सिं०को०कं०लि० के मामले में औसत कीमत उसकी वर्ष 1992-93 की उत्पादन की औसत लागत से कम थी ।

सेंट्रल कोलफी ल्ड्स लि० के उत्पादन में वृद्धि

4290. **श्री दिलीप सिंह जुदेव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोल फील्ड्स लि० ने कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अपनी उत्पादन क्षमता 24.30 लाख टन तक बढ़ा ली है ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कुल कितनी कोयला खनन परियोजनाएं पूरी की गई है ;

(ग) चालू खनन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) इन खनन परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात् कोयला उत्पादन का परिमाण कितना हो जाएगा; और

(ङ) इन खनन परियोजनाओं से कोयले की कितनी मांग पूरी होगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ने 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार 34 खनन परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, जिनसे वर्ष 1993-94 के दौरान प्रतिवर्ष कुल 24.70 मि० टन कोयले का उत्पादन प्राप्त हो रहा है ।

(ग) और (घ) सें०को०लि० में 26 चालू खनन परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 20.44 मि० टन प्रतिवर्ष की है, जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है ।

(ङ) सें०को०लि० से संयोजित कोयले की मांग को पूर्णतः पूरा किया जा रहा है ।